भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2793
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश

†2793. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रमुख अपतटीय तेल भंडारों की खोज में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या निजी कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे निवेश से तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा अन्वेषण गतिविधियों के लिए खोला गया कुल क्षेत्र पहले 'नो-गो एरिया' के अंतर्गत था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार ने प्रमुख अपतटीय तेल भंडारों के अन्वेषण में निवेश को सुविधाजनक बनाने, हाइड्रोकार्बन उत्पादन बढ़ाने और निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहले की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. दिनांक 30 मार्च, 2016 को भारतीय अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण रकबा आवंटित करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) की अधिसूचना। इस वर्ष उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था की ओर ऐतिहासिक बदलाव भी किया गया।

ii. वर्ष 2015 में सरकार ने खोजे गए रकबों को प्रदान करने तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की गैर-मौद्रिकीकृत खोजों के मुद्रीकरण को सक्षम बनाने के लिए खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति की शुरुआत की।

iii. सरकार ने वर्ष 2016 और 2017 में विपणन के लिए नीतियों को अधिसूचित किया, जिसमें गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता शामिल है, जो वैकल्पिक ईंधन के कुल मूल्य के आधार पर अधिकतम मूल्य के अधीन है।

iv. सरकार ने जुलाई, 2022 में घरेलू रूप से उत्पादित क्रूड ऑयल की बिक्री को विनियमित किया।

v. इसके अतिरिक्त, सरकार ने व्यापार में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2019 को नीति सुधारों को अधिसूचित किया। (अप्रत्याशित लाभ के मामले को छोड़कर श्रेणी II और III प्रकार के बेसिनों से राजस्व हिस्सेदारी को हटा दिया गया था, गहरे और अत्यधिक गहरे ब्लॉकों के लिए 7-वर्षीय रॉयल्टी अवकाश और रियायती रॉयल्टी दरों, क्षेत्रों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता)।

vi. एचईएलपी के तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) के अंतर्गत, अब तक आठ ओएएलपी बोली दौर संपन्न हो चुके हैं और 3.37 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल अनुमानित निवेश के साथ ईएंडपी गतिविधियों के लिए 144 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। ओएएलपी बोली दौर-IX में, पेश किए गए 28 ब्लॉकों में से 19 ब्लॉक अपतटीय क्षेत्र में हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 1,22,721 वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) है।

vii. सरकार अंडमान और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग जैसे अपतटीय तलछटी बेसिन के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण पर भी काफी खर्च कर रही है। सरकार ने मौजूदा ईईजेड सीमा से आगे, भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ईसीएस) में 30,000 एलकेएम भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

viii. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी, 2017 की स्थापना ।

ix. वर्ष 2022 में, भारत सरकार ने नए अन्वेषण के लिए अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 1 मिलियन एसकेएम 'नो- गो' क्षेत्र (जो पहले ईएंडपी संचालन के लिए प्रतिबंधित था) को खोल दिया।

x. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018 ।

xi. जून, 2020 में, सरकार ने परियोजना की पूर्ण निर्माण अवधि को कम करने में सहायता करने और निवेशकों को प्रारंभिक चरण में राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए अन्वेषण अवधि के दौरान ही प्रारंभिक चरण की खोज के मुद्रीकरण की अनुमति दी।

xii. नवंबर, 2021 में सरकार ने ऐसी गैस बनाने के लिए तदर्थ और परीक्षण गैस के मुद्रीकरण की अनुमति दी, जो फ्लेयर्ड गैस है और बाजार में उपलब्ध होगी।

xiii. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तेल और गैस ब्लॉकों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी लाना और स्व- प्रमाणन के आधार पर कई प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।

तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाएं उच्च जोखिम, पूंजी परक और प्रौद्योगिकी गहन हैं। भारत में 26 तलछटी बेसिन हैं। सरकार ने मूल्यांकित नहीं किए गए तलछटी बेसिन क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन पुन: आंकलन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम आदि शामिल हैं। तेल और गैस का अन्वेषण सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में कंपनियों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों सहित अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी में योगदान दे सकती हैं।

(ग): "नो-गो" क्षेत्र, जो ईएंडपी प्रचालन के लिए प्रतिबंधित था, को अब 1,366,708 एसकेएम से घटाकर 24,832 एसकेएम कर दिया गया है, जिससे अन्वेषण गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती "नो-गो" क्षेत्र का लगभग ~99% हिस्सा खुल गया है।

ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत के तट से दूर स्थित हैं।

****